बिहार विधानसभा चुनाव : मोदी-नीतीश के लिए अग्निपरीक्षा

मनोज कुमार झा -वीणा भाटिया

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है। एक तरह से चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। दरअसल, यह चुनाव भाजपा के साथ ही नीतीश कुमार के लिए भी अग्निपरीक्षा की तरह है। इस चुनाव से यह तय हो जाएगा कि नीतीश.लालू गठबंधन में कितना दम है और क्या वे भाजपा के विकास रथ को रोक पाने में समर्थ हैं या नहीं वहीं, दूसरी ओर बिहार में जीत के लिए भाजपा भी कोई कोर.कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। वैसे, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरा होने के बाद उसकी लोकप्रियता का ग्राफकाफी तेजी से गिरा है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है और लोगों को लग रहा है कि वे छले गए हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भाजपा को दिल्ली में भारी हार का सामना करना पड़ा और पश्चिम बंगाल में भी उसे सफलता नहीं मिली। ये अलग बात है कि वहां मोदी ने ममता से हाथ मिला लिया है। बिहार में जीत भाजपा के लिए बहुत मायने रखती है। बिहार के बाद यूपी पर उसकी नज़र है। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां चुनावी सफलता मिलने के बाद भाजपा को राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाएगा और वह अपना मिशन आसानी से पूरा कर पाएगी। इसलिए मोदी.अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सफलता हासिल करने के लिए एड़ी.चोटी का जोर लगा रहे हैं। यह अलग बात है कि बिहार में भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है और इसीलिए चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। वहीं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं कोई सवाल और संशय नहीं है। पर भाजपा के साथ ऐसी बात नहीं है। मोदी की गिरती लोकप्रियता के कारण उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

भूलना नहीं होगा कि बड़े पैमाने पर प्रचार के बल पर ही मोदी केंद्र की सत्ता में आ सके। विकल्पहीनता भी इसके पीछे एक बड़ी वजह रही। पर नरेंद्र मोदी ने जनता को जो सपने दिखाए थे, सारे झूठे साबित हुए। अब जनता के एक बड़े हिस्से के सामने स्पष्ट है कि मोदी सरकार की सभी नीतियां बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली हैं। इसी बीचए स्वच्छता अभियान, योग और रेडियो पर मन की बात करने के साथ उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फ़ी विद डॉटर

बिहार की चुनावी राजनीति पूरी तरह जातिवादी समीकरणों पर आधारित रही है। लालू जहां यादवों के नेता रहे हैं, नीतीश का प्रभाव कुर्मी.कोयरी जाति के वोटरों में माना जाता है। जदयू का वोट बैंक ओबीसी रहा है। साथ में मुसलमान वोटर हैं ही। राज्य का मुस्लिम वोटर कभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं जा सकता। जातिवादी समीकरण और भी उभर कर आएं और नीतीश पर माफ़िया का सहयोग लेने का आरोप न लगेए संभवतः इसे देखते हुए ही जदयू विधायक अनंत सिंह और सुनील पांडे को क़ानून की गिरफ्त में ले लिया गया है। अनंत सिंह नीतीश का बहुत बड़ा सहयोगी रहा है और सुनील पांडे के तार कुख्यात रणवीर सेना से जुड़े रहे हैं। ऐन चुनाव के पहले इन्हें सींखचों के भीतर करने के पीछे जदयू की खास रणनीति हो सकती है। नीतीश कुमार अपनी छवि साफसुथरी पेश करना चाहते हैं। खास बात ये है कि ये माफ़िया तत्व भाजपा को किसी तरह का लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इस चुनाव में लालू भी अपना पूरा दम.खम लगा देंगे, क्योंकि चुनाव जीतने की स्थिति में वह सत्ता में अपने परिवार की भागीदारी सुनिश्चित करा सकेंगे, अन्यथा उनके परिवार की राजनीतिक वंशबेल सूख जाएगी।

जैसे कुछ प्रोग्राम पेश किएए उससे भी उनकी छवि धूमिल हुई है। नरेंद्र मोदी का अब तक जो रवैया रहा है, विदेशों में उन्होंने जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, यहां तक कि सरकारी योजनाओं का प्रचार करने वह स्वयं टीवी पर आ रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म हो गई है। लेकिन भाजपा और संघ को यह लगता है कि साम-दाम-दंड.भेद की नीति अपना कर वह बिहार की सत्ता पर काबिज़ हो सकेगी। लेकिन सवाल है, क्या मोदी-अमित शाह और सबसे बढ़ कर संघ का यह सपना पूरा हो सकेगा।

बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार-लालू यादव और कांग्रेस के साथ ही वामपंथियों के लिए भी जीवन-मरण का सवाल है। अगर भाजपा किसी भी तरह बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाती है तो फिर नीतीश.लालू का उभर कर आ पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार प्रचार युद्ध में किसी भी कीमत पर भाजपा से पीछे नहीं रहना चाहते। उन्होंने हर घर दस्तक योजना शुरू की है जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वयं और जदयू.राजद एवं अन्य सहयोगी दलों के नेता.कार्यकर्ता घर.घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि चुनाव में जीत आक्रामक प्रचार पर ही निर्भर है, इसलिए वह जहां तक हो सकेगा, इसके लिए संसाधन झोंकने में पीछे नहीं रहेंगे। कहा जा रहा है कि नीतीश भी इस बार हाईटेक चुनाव प्रचार अभियान चलाएंगे। इस बीच, विधान परिषद् चुनाव में जदयू को बहुत कम सीटें मिलीं और भाजपा का प्रदर्शन बढ़िया रहा। इससे बहुतों को लग रहा है कि यह नीतीश के नेतृत्व की कमजोरी है, लेकिन विधान परिषद् के चुनावी गणित और विधानसभा के चुनावी समीकरणों में बुनियादी अंतर को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

नीतीश की यह एक बड़ी ग़लती मानी जा रही है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के बढ़िया प्रदर्शन नहीं करने पर इस्तीफ़ा दे दिया और जीतन राम मांझी को डमी मुख्यमंत्री बना दिया जो उनके लिए घातक साबित हुए। जब तक नीतीश को यह बात समझ में आई, मांझी को जितना नुकसान करना था, कर गए। अब वे भाजपा के साथ हैं। इसी प्रकार, लालू प्रसाद से अलग हुए पप्पू यादव भी भाजपा के पाले में चले गए हैं। पर इस बाहुबली का प्रभाव अब नहीं के बराबर रह गया है। मांझी भी भाजपा की नैया किस हद तक खे सकेंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि महादलित के सारे वोट अपने हाथ में होने का दावा वह नहीं कर सकते।

बिहार की चुनावी राजनीति पूरी तरह जातिवादी समीकरणों पर आधारित रही है। लालू जहां यादवों के नेता रहे हैं, नीतीश का प्रभाव कुर्मी.कोयरी जाति के वोटरों में माना जाता है। जदयू का वोट बैंक ओबीसी रहा है। साथ में मुसलमान वोटर हैं ही। राज्य का मुस्लिम वोटर कभी भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं जा सकता। जातिवादी समीकरण और भी उभर कर आएं और नीतीश पर माफ़िया का सहयोग लेने का आरोप न लगेए संभवतः इसे देखते हुए ही जदयू विधायक अनंत सिंह और सुनील पांडे को क़ानून की गिरफ्त में ले लिया गया है। अनंत सिंह नीतीश का बहुत बड़ा सहयोगी रहा है और सुनील पांडे के तार कुख्यात रणवीर सेना से जुड़े रहे हैं। ऐन चुनाव के पहले इन्हें सींखचों के भीतर करने के पीछे जदयू की खास रणनीति हो सकती है। नीतीश कुमार अपनी छवि साफसुथरी पेश करना चाहते हैं। खास बात ये है कि ये माफ़िया तत्व भाजपा को किसी तरह का लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। इस चुनाव में लालू भी अपना पूरा दम.खम लगा देंगे, क्योंकि चुनाव जीतने की स्थिति में वह सत्ता में अपने परिवार की भागीदारी सुनिश्चित करा सकेंगे, अन्यथा उनके परिवार की राजनीतिक वंशबेल सूख जाएगी।

जनता परिवार के महाविलय का साकार न हो पाना गैरभाजपा दलों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर यदि महाविलय हो भी जाता तो बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से इसका कोई खास महत्व नहीं होता। गठबंधन में शामिल अन्य दल बिहार के वोटरों पर शायद ही कोई असर डाल पाते। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ओबीसी वोट पूरी तरह उन्हें ही मिलें। साथ ही, कांग्रेस और वामपंथी भी कुछ सीटें जीत पाने में कामयाब हो सकें।

भाजपा जातिवादी समीकरणों के ध्यान में रखते हुए नई चाल चलने की कोशिश में है। संघ के रणनीतिकारों को यह समझ में आ गया है कि बिहार में साम्प्रदायिक एजेंडा कारगर नहीं हो सकेगा। ऐसा करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर चुनाव के ऐन पहले संघ ने बिहार में साम्प्रदायिक वैमनस्य फैला कर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की तो नीतीश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, इसलिए अब उन्हें पिछड़ा नेता बताने की कवायद चल रही है। जोर.शोर से घोषित किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या इससे पिछड़ा वर्ग का मतदाता भाजपा को वोट देगा या वह अपने क्षेत्रीय नेताओं पर ही भरोसा करना पसंद करेगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुलकर सांप्रदायिक कार्ड खेला और अब बिहार में जातिवादी कार्ड खेलने की कोशिश में है, यह बात लोगों की समझ में आ रही है। जहां तक विकास का सवाल है, तो लोगों को यह पता चल चुका है कि मोदी सरकार का विकास का जो एजेंडा है, वह आम जनता के विकास का नहीं, बल्कि देश के बड़े पूंजीपतियों के विकास का है। मोदी सरकार का छल जनता के सामने आ चुका है। यही कारण है कि जब उन्हें देश का पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बताया गया तो इसकी हंसी ही उड़ी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा का रंग गिरगिट की तरह बदलता रहा है। ये चुनावी सफलता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। वहींए नीतीश जो सुशासन बाबू के रूप में जाने गएए आम जनता के लिए आदर्श विकल्प नहीं कहे जा सकते। दरअसल, आज विकल्पहीनता का निर्वात ही वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के गहरे संकट को दर्शा रहा है। पर जहां चुनाव के विकल्प सीमित हों तो जनता को कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बिहार.यूपी जहां भाजपा के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, वहीं मध्यमार्गी दलों के लिए खुद के अस्तित्व को बचाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती। देखना है, इस चुनाव में राजनीति के कैसे.कैसे रंग सामने आते हैं।

तुर्की-ब-तुर्की / भ्रष्टाचार तथा रोजगार का घोटाला मोदी के लिए गौण

केन्द्रीय कानून मन्त्री सदानंद गौड़ा ने व्यापमं घोटाले पर प्रधनमंत्री की चुप्पी का बचाव यह कहते हुए किया कि छोटी-छोटी बातों पर प्रधानमंत्री वक्तव्य नहीं दिया करते। गौड़ा के अनुसार यह घोटाला प्रधानमंत्री के स्तर का नहीं है।

हमारा कहना है-

- बात तो आपने खरी कही गौड़ा जी! व्यापमं भ्रष्टाचार और सरकारी रोज़गार का घोटाला है। ये दोनों ही मुद्दे आपकी मोदी सरकार के लिये गौण हैं। क्योंकि न कार्पोरेट जगत को और न भाजपा के संघी आकाओं को इन मुद्दों से कुछ लेना-देना है। लिहाज़ा क्या ताज्जुब कि आप लोग़ों के नजरिये से व्यापमं एक ऐसा मुद्दा भी नहीं जिस पर मोदी जी को बोलने की जरूरत हो। यह बात और है कि ऐसा ही मुग़ालता आपसे पहले वाली सरकार को भी था और इस देश की जनता ने उनको सही नसीहत दे दी थी।
- शायद आपको भी याद हो गौड़ा जी कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी भ्रष्टाचार और रोज़गार के मुद्दों पर बहुत बोला करते थे। यहां तक कि तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वे मोनीमोहन सिंह कह कर बुलाया करते थे। क्या अब उन्होंने अपना नाम नरेन्द्र मोदी से मोनेंद्र मोदी कर लिया है ? कहते हैं कि बोले बिना वे रह नहीं सकते और इसी लिये जब देखो तब वे विदेश यात्रा पर निकल पड़ते हैं ताकि वे अपने बोलने की खुरक बाहर ही निकाल सकें।
- कहीं ऐसा तो नहीं कि वे व्यापमं घोटाले पर इसलिये नहीं बोलना चाहते कि उन्हें मजबूरन शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बोलना पड़ेगा। आप भी जानते ही होंगे गौड़ा जी चौहान को धूल चटाने में मोदी की दिलचस्पी कांग्रेसियों से भी ज़्यादा है। लिहाज़ा, जब दिग्विजय सिंह एंड कम्पनी उनका अभीष्ट पूरा कर ही रहे हैं तो उन्हें बोलने की क्या जरूरत ?
- लगे हाथ यह भी बता दीजिये कि मोदी के लिये बड़े मुद्दे क्या हैं जिनके लिये वे बोलना चाहेंगे ? मंहगाई पर वे बोलते नहीं; साम्प्रदायिक दंगों पर वे बोलते नहीं; उत्तर-पूर्व और काशमीर समस्या पर वे बोलते नहीं; स्त्री सुरक्षा और बालश्रम पर वे बोलते नहीं; ललित मोदियों और वसुंधरा राजो पर भी नहीं बोलते। जुमलेबाज़ी चाहे जितनी करा लो। जुमलों से वे देश की गंदगी साफ़ करा देते हैं। जुमलों से वे काला धन समाप्त कर देते हैं। जुमलों से वे जन-जन को धनी बना देते हैं। जुमलों से वे भारत को दुनिया का सिरमौर सिद्ध कर देते हैं। जाहिर है व्यापमं जैसे व्यापकतम घोटाले जुमलों से तो हल हो नहीं सकते। लिहाज़ा मोदी का चुप रहना, जैसा कि आपने कहा, नितांत स्वाभाविक है।